

## प्रेस विज्ञप्ति

अहमदाबाद, 1 दिसंबर, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, श्रीमति प्रियंका चतुर्वेदी, कन्वीनर, एआईसीसी कम्युनिकेशंस; श्री पवन खेडा व श्री मनीष दोशी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

मोदी सरकार आए दिन 'राष्ट्रहित' व 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों की खरीद में एक 'बड़े घोटाले' की बू आ रही है। सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान की गंभीर शंकाओं के सार्वजनिक होने के बावजूद सरकार इस पूरे मामले में साजिशी चुप्पी साधे हुए है।

मोदी सरकार द्वारा फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन से 36 'राफेल लड़ाकू विमानों' की खरीद में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। इस पूरे मसौदे की बिसात गैरपारदर्शिता; 'रक्षा सौदों की प्रक्रिया' में अनिवार्य प्रावधानों को ताक पर रखने; ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलॉजी में देशहित को छोड़ सरकारी पीएसयू 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' के अधिकारों को हानि पहुंचाने व अपने 'पूँजीपति मित्रों' को बेतहाशा फायदा देने पर बिछी है।

सर्वमान्य तथ्य:

- I. **20.08.2007** : यूपीए सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए 126 लड़ाकू जहाजों की खरीद का टेंडर जारी किया गया। व्यवसायिक मंत्रणा के बाद लड़ाकू जहाज बनाने वाली दो कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया - राफेल व यूरो फाईटर टाईफून।
- II. **12.12.2012** : राफेल लड़ाकू जहाज US\$10.2 बिलियन (2012 के एक्सचेंज के मुताबिक लगभग ₹54000 करोड़) के 'बेस प्राईस' के साथ एल-1 वेंडर बना। शर्तों के मुताबिक 18 लड़ाकू जहाज 'पलाई अवे कंडीशन' यानि फ्रांस में संपूर्णतः निर्मित हो वायुसेना को मिलने थे। 126 में से बाकी 108 लड़ाकू जहाज ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलॉजी के साथ भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने थे। इसके अलावा एक शर्त यह भी थी कि कुल मसौदे की कीमत के बराबर का 50 प्रतिशत निवेश भारत में करना अनिवार्य होगा।
- III. **13.03.2014** : हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड व राफेल बनाने वाली कंपनी डैसॉल्ट एविएशन में 'वर्क शेयर एग्रीमेंट' हुआ। इसके मुताबिक भारत में बनने वाले 108 लड़ाकू जहाजों का 70 प्रतिशत काम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा व 30 प्रतिशत काम डैसॉल्ट एविएशन द्वारा।
- IV. **26.05.2014** : मोदी सरकार ने देश की सत्ता सम्हाली।
- V. **04.07.2014** : दूसरा लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी 'यूरो फाईटर टाईफून' ने देश के रक्षामंत्री, श्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर कहा कि (क) वे 126 टाईफून लड़ाकू जहाज 20 प्रतिशत कम कीमत यानि €138 मिलियन प्रति जहाज (कुल लागत €17.5 बिलियन) पर देने को तैयार हैं; (ख) वे ये जहाज 'ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलॉजी' तथा हथियारों सहित देंगे; (ग) भारत में

बनने वाले जहाजों से 20,000 नौकरियां भी देने का वायदा किया। इस पत्र की कॉपी संलग्नक A1 संलग्न है।

- VI. **10.04.2015** : प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए और वहां अचानक फ्रांस में निर्मित 36 राफेल लड़ाकू जहाज खरीदने के निर्णय की घोषणा कर डाली। न तो भारत सरकार की 'कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी' से खरीद की अनुमति ली गई और न ही रक्षा सौदों की अनिवार्य प्रक्रिया (डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर) को देखा गया और न ही किसी संस्था से राय मशवरा किया गया। हां, उस समय रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के मालिक, श्री अनिल अंबानी जरूर पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे।
- VII. **30.07.2015** : मोदी सरकार ने 126 लड़ाकू विमानों की खरीद का यूपीए सरकार के समय का टेंडर खारिज कर दिया।
- VIII. **23.09.2016** : मोदी सरकार द्वारा 36 राफेल लड़ाकू जहाजों की खरीद का लिखित समझौते पर दस्तखत किए जिनकी कीमत मीडिया खबरों व सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग US\$ 8.7 बिलियन (₹ 59,629 करोड़— एक्सचेंज रेट के मुताबिक) निर्धारित हुई।
- IX. **03.10.2016** : श्री अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड व राफेल लड़ाकू जहाज बनाने वाली डैसॉल्ट एविएशन में रक्षा उत्पाद बनाने बारे समझौता हुआ।
- X. **16.02.2017** : रिलायंस डिफेंस लिमिटेड की सब्सिडियरी व डैसॉल्ट एविएशन में भारत में एक ज्वाइंट वेंचर समझौता हुआ। कंपनी की वेबसाइट पर स्पष्ट लिखा है कि कंपनी 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे में 30,000 करोड़ का ऑफसेट डिफेंस प्रोडक्शन का काम कर रही है। इसकी कॉपी संलग्नक A2 संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू जहाज 60,000 करोड़ में खरीदने का सौदा किया।

### समय आ गया है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को जवाब दें:-

1. क्या कारण है कि मोदी सरकार 36 राफेल लड़ाकू जहाज इतनी महंगी कीमत पर खरीद रही है? क्या यह सही है कि यूपीए सरकार ने 126 राफेल लड़ाकू जहाज (ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलॉजी सहित) अमेरिकी डॉलर 10.2 बिलियन के बेस प्राइस पर खरीदने का मसौदा किया था? क्या यह भी सच है कि मोदी सरकार उन्हीं 36 लड़ाकू जहाजों को (ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलॉजी के बगैर) अमेरिकी डॉलर 8.7 बिलियन में खरीद रही है?  
क्या यह सही नहीं कि इस प्रकार से यूपीए द्वारा खरीदे जाने वाले एक जहाज की कीमत US\$ 80.95 मिलियन (₹526.1 करोड़) आती, जबकि मोदी सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले एक जहाज की कीमत US\$ 241.66 मिलियन (₹ 1570.8 करोड़) आएगी? अगर यह सही है, तो राजस्व को हुई हानि का कौन जिम्मेदार है? अगर उपरोक्त सही नहीं, तो भाजपा राफेल जहाज की कीमत बताने से क्यों गुरेज कर रही है?
2. प्रधानमंत्री ने फ्रांस में निर्मित 36 राफेल लड़ाकू जहाजों को खरीदने का एकछत्र निर्णय कैसे लिया, जबकि 10 अप्रैल, 2015 को न तो 'कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी' की मंजूरी ली गई थी और न ही अनिवार्य 'डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, 2013' की अनुपालना की गई थी? जब

भारत सरकार की 'कॉन्ट्रैक्ट नेगोसिएशन कमेटी' व 'प्राईस नेगोसिएशन कमेटी' द्वारा इस खरीद की अनुमति नहीं थी, तो प्रधानमंत्री 10 अप्रैल, 2015 को ऐसा एकछत्र निर्णय कैसे ले सकते थे?

3. मोदी सरकार ने आज तक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलॉजी, जो कि भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिल रही थी, दरकिनार क्यों किया? क्या यह राष्ट्रहित में उठाया गया सही कदम है?
4. क्या यह सही नहीं कि 10 अप्रैल, 2015 को छत्तीस लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले से पहले 4 जुलाई, 2014 को यूरो फाईटर टाईफून कंपनी ने देश के रक्षामंत्री को 20 प्रतिशत कम कीमत पर तथा 'ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलॉजी' व हथियारों सहित जहाज बेचने का ऑफर दिया था? फिर क्या कारण था कि यूरो फाईटर टाईफून लड़ाकू जहाज के इस ऑफर का संज्ञान नहीं लिया गया? क्या रक्षामंत्री व प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि दोनों लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनियों से नेगोशिएट कर सबसे कम रेट का निर्धारण करते?
5. क्या कारण है कि एक सरकारी पीएसयू – हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के हितों की अनदेखी प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई? जब 13 मार्च, 2014 को 'डिफेंस ऑफसेट' का काम करने का समझौता राफेल बनाने वाली डैसॉल्ट एविएशन व हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में हो गया था, तो फिर किन कारणों से इस समझौते को खारिज कर डैसॉल्ट एविएशन द्वारा रिलायंस के साथ यह समझौता कर लिया गया? क्या सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सीधे-सीधे 30,000 करोड़ रु. के अनुबंध मिलने की हानि नहीं हुई?
6. क्या रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में रिलायंस व डैसॉल्ट एविएशन के बीच हुए सबसे बड़े समझौते को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड व देश के मंत्रीमंडल से संस्थागत अनुमति मिली? यदि नहीं, तो क्या प्रधानमंत्री इसका कारण बताएंगे?